राजस्थान में विधानसभा चुनाव एवं मतदान व्यवहार : विश्लेषणात्मक अध्ययन

डॉ॰ शैलेन्द्र मौर्य

शोध सारांश

भारत विश्व का सबसे बडा लोकतन्त्र है। लोकतन्त्र को जीवन्त बनाये रखने के लिए स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन व्यवस्था महत्वपूर्ण है, क्योंकि लोकतन्त्र और निर्वाचन अन्योन्याश्रित है। निर्वाचन मुक्त और निष्पक्ष हो सके इसलिए निर्वाचन एक स्वतन्त्र प्राधिकरण के अधीक्षण और निर्देश के अधीन कराए जाते हैं। अतः भारतीय संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324-329 के अनुसार निर्वाचन व्यवस्था का प्रतिपादन किया गया है। निर्वाचन आयोग भारत में निर्बाध एवं निष्पक्ष निर्वाचन प्रक्रिया को सुनिश्चित करता है। निर्वाचन प्रकिया में अधिकाधिक जन सहभागिता ही लोकतन्त्र को सुदृढता प्रदान करती है। जन सहभागिता के आंकलन का आधार मतदान प्रतिशत होता है। किसी भी निर्वाचन में मतदान प्रतिशत मतदान व्यवहार द्वारा ही निर्धारित होता है। मतदान व्यवहार के अध्ययन के अन्तर्गत उन स्थितियों एवं कारणों का अध्ययन किया जाता है, जो एक मतदाता के व्यवहार अर्थात मतदाता के निर्णय को प्रभावित करते हैं।

मूल शब्द : लोकतन्त्र, निर्वाचन, जन सहभागिता, मतदान तथा मतदान व्यवहार

Corresponding Author

सहायक आचार्य, राजनीति विज्ञान विभाग,राजकीय महाविद्यालय सिरोही, राजस्थान
email :drshailendarmaurya@gmail.com

प्रस्तावना

लोकतंत्र समकालीन राजनीति के अध्ययन की एक चर्चित संकल्पना है। लोकतन्त्र के सन्दर्भ में चुनाव-राजनीति, उम्मीदवार, मतदाता तथा मतदान व्यवहार राजनीतिक अध्ययन की प्रमुख संकल्पनाएं है। लोकतान्त्रिक व्यवस्थाओं में प्रत्येक व्यस्क नागरिक द्वारा सरकार के निर्णयों, नीतियों और योजनाओं, विभिन्न राजनीतिक दलों की चुनावी घोषणाओं और कार्यक्रमों अथवा चुनाव लड़ रहे उम्मीदवार के बारे में अपनी सहमति अथवा असहमति को प्रकट करने के माध्यम से रूप में 'मतदान' का अत्यधिक महत्व होता है। अतः लोकतान्त्रिक व्यवस्थाओं में अपने मत

की अभिव्यक्ति के रूप में 'मतदान' का विशिष्ठ महत्व होता है। मतदान आचरण अथवा मतदान व्यवहार समकालीन लोकतान्त्रिक राजनीति की एक चर्चित अवधारणा है।

मतदान व्यवहार

निर्वाचन राजनीति में मतदान-व्यवहार का अध्ययन एक महत्वपूर्ण विषय बन गया है। मतदान व्यवहार के अध्ययन के अन्तर्गत उन स्थितियों एवं कारणों का अध्ययन किया जाता है, जो एक मतदाता के व्यवहार अर्थात मतदाता के निर्णय को प्रभावित करते हैं। मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाली स्थितियाँ एवं कारक सार्वभौमिक नहीं होते हैं। अर्थात ये कारक एवं तथ्य प्रत्येक स्थिति में प्रत्येक मतदाता पर एक सा प्रभाव नहीं डालते हैं। एक स्थिति में एक मतदाता का व्यवहार दूसरे मतदाता के व्यवहार से भिन्न हो सकता है। मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाले तत्व भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न हो सकते है। इसलिए सभी क्षेत्रों में मतदान व्यवहार समान नहीं होता है।

चुनाव से पूर्व और चुनाव के पश्चात् मतदाताओं से सम्पर्क स्थापित कर विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और उसी आधार पर मतदान व्यवहार के सम्बद्ध में कुछ निष्कर्ष प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है।[1] इस प्रकार राजनीतिक प्रक्रियाओं विशेष रूप से निर्वाचन प्रक्रियाओं के सम्बन्ध में मतदान व्यवहार एक महत्वपूर्ण अवधारणा है।

मतदान व्यवहार अथवा मतदान आचरण चुनाव एवं चुनावी प्रक्रिया से संबंधित व्यवहार है, जो अनेक सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक कारणों से प्रभावित होता है।[2]

मतदान व्यवहार का अर्थ

मतदान व्यवहार से तात्पर्य एक मतदाता के उस चुनाव-व्यवहार से है, जिसका प्रदर्शन वह चुनाव अभियान एवं मतदान में करता है।[3] चुनाव एंव निर्वाचणीय प्रक्रिया से संबंधित एक अन्य पहलू मतदान आचरण है। डोनाल्ड ई. स्टोक्स के अनुसार मतदान व्यक्तिगत प्राथमिकताओं व सामूहिक निर्णयों में समहार करने का एक साधन है।[4] मतदान व्यवहार का आशय है कि मतदाता अपने मताधिकार के प्रयोग में किन तत्वों से प्रभावित होता है। अतः मतदाता के मतदान करते समय उनके व्यवहार का अध्ययन ही मतदान व्यवहार करता है। मतदान व्यवहार में इस बात का अध्ययन किया जाता है कि किन तत्वों से प्रभावित होकर व्यक्ति एक विशेष उम्मीदवार और एक

विशेष राजनीतिक दल के पक्ष में अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं। इस दृष्टि से मतदान व्यवहार का अध्ययन चुनाव के पूर्व भी किया जाता है और चुनाव के बाद भी।[5]

राजस्थान में विधानसभा चुनाव एवं मतदान व्यवहार

स्वाधीन भारत में संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार राजस्थान में पहली विधानसभा के गठन के लिए चुनाव फरवरी, 1952 में सम्पन्न हुए और 29 मार्च, 1952 को राज्य की पहली विधान सभा का गठन हुआ।[6] पहली विधानसभा के गठन के लिए प्रथम आम चुनाव का आयोजन प्रदेश में लोकतान्त्रिक सरकार के गठन के लिए निर्वाचन राजनीतिक व्यवस्था प्रारम्भ भी था। अर्थात राजस्थान में निर्वाचन राजनीतिक व्यवस्था का प्रारम्भ मतदान व्यवस्था का भी प्रारम्भ था। चुकि चुनावी लोकतंत्र की बुनियाद नागरिकों का विवेकपूर्ण निर्णय होता है।[7] अतः प्रदेश में मतदान व्यवहार की स्थिति के अध्ययन के लिए विधान सभा चुनावों का अध्ययन आवश्यक है।

पहली विधानसभा आम चुनाव 1952

प्रदेश की प्रथम लोकतात्रिक सरकार के गठन के लिए प्रथम विधान सभा आम चुनाव फरवरी 1952 में सम्पन्न हुए। प्रथम विधानसभा की 160 सीटों के लिए कुल 757 उम्मीदवारों ने चुनाव में भाग लिया।[8] इसमें छोटे-बड़े सभी राजनीतिक दलों के 449 उम्मीदवारों के साथ 308 स्वतन्त्र/निदर्लीय उम्मीदवारों ने चुनाव में सहभागिता की। कांग्रेस सहित 11 अन्य राजनीतिक दलों ने इस निर्वाचन प्रक्रिया में भाग लिया। कांग्रेस ने विधानसभा की कुल 160 सीटों में से 102 स्थानों पर जीत दर्ज की। इसके अलावा प्रथम विधानसभा आम चुनाव में जनसंघ ने 11 स्थान, समाजवादी दल ने 1 स्थान, राम राज्य परिषद ने 24 स्थान, हिन्दू महासभा ने 2 स्थान, के.एम.पी. पी. ने 1 स्थान, कृषीकर लोक पाटऍ ने 7 स्थान, पुरूषार्थी पंचायत ने 3 स्थान एवं निर्दलियों ने 39 स्थान प्राप्त किये।[9] कांग्रेस ने विधान सभा के कुल स्थानों में से लगभग 54 प्रतिशत (53.68) स्थानों पर विजय दर्ज की। यदि मतदान की दृष्टि से देखा जाये तो कांग्रेस ने कुल वैध कुल मतदान 34,46,239 में से 13,38,394 मत अर्थात् 39.71 प्रतिशत मत प्राप्त किये। राष्ट्रीय आन्दोलन में कांग्रेस की भूमिका एवं जयनारायण व्यास, टीका राम पालीवाल और मोहनलाल सुखाडिया जैसे ओजस्वी नेतृत्व के कारण प्रथम आम चुनाव में मतदान व्यवहार कांग्रेस के पक्ष में रहा।

दुसरी विधान सभा चुनाव-1957

प्रदेश विधानसभा की कुल 176 सीटों के लिए सम्पन्न द्वितिय आम चुनाव 1957 में कुल 653 उम्मीदवारों ने सहभागित की। इस चुनाव विभिन्न राजनीतिक दलों के 328 उम्मीदवारों के साथ 325 स्वतन्त्र/निदर्लीय उम्मीदवारों ने सहभागिता की। कांग्रेस ने विधानसभा की कुल 176 सीटों में से 119 स्थान, जनसंघ ने 6 स्थान, समाजवादी दल (सी.पी.आई) ने 1 स्थान, रामराज्य परिषद को 17, पी.एस.पी. ने 1 एवं निर्दलियों ने 39 स्थान प्राप्त किये। काग्रेस ने विधान सभा के कुल स्थानों में से लगभग 68 प्रतिशत (67.61) स्थानों पर विजय दर्ज की। यदि मतदान की दृष्टि से देखा जाये तो कांग्रेस ने कुल वैध कुल मतदान 47,46,461 में से 21,41,924 मत अर्थात् 45.13 प्रतिशत मत प्राप्त किये।[10]

प्रदेश में कांग्रेस सरकार के पांच वर्षों (1952-1957) के कार्यकाल में 3 बार नेतृत्व परिवर्तन ने मतदान व्यवहार को नकारात्मक रूप से प्रभावित नही किया बल्कि प्रदेश की जनता ने कांग्रेस दल पर पहले की अपेक्षा अधिक विश्वास व्यक्त किया। अतः कांग्रेस को पहली विधानसभा में प्राप्त स्थानों (102) से 17 अधिक स्थान अर्थात 119 स्थानों पर सफलता प्राप्त हुई।[11] सम्भवतः प्रदेश की जनता ने प्रादेशिक नेतृत्व की अपेक्षा राष्ट्रीय नेतृत्व (पण्डित नहेरू) पर विश्वास व्यक्त करते हुए शासन की बागडोर पुनः कांग्रेस को सौंपी।

तीसरी विधानसभा चुनाव-1962

प्रदेश विधानसभा की 176 सीटों के लिए आम चुनाव वर्ष 1962 में सम्पन्न हुए। इस चुनाव में 8 राजनीतिक दलों के 500 उम्मीदवारों सहित 390 निर्दलिय उम्मीदवारों अर्थात कुल 890 उम्मीदवारों ने सहभागिता की। कांग्रेस ने 88 स्थान, जनसंघ ने 15 स्थान, पी.एस.पी. ने 2 स्थान, राम राज्य परिषद ने 3 स्थान, सी.पी.आई. ने 5 स्थान, एस.डब्लू.टी. ने 36 स्थान, समाजवादी पाटऍ ने 5 स्थान एवं निर्दलियों ने 22 स्थान प्राप्त किये। कांग्रेस ने राज्य विधानसभा के कुल 176 स्थानों में से 50 प्रतिशत स्थानों पर जीत दर्ज की।[12] यदि मतदान की द्वष्टि से देखा जाये तो कांग्रेस ने कुल वैध मतदान (51,32,763) में से 39.98 प्रतिशत (20,52,383) मत प्राप्त किये जबकि दूसरे विधानसभा आम चुनाव 1957 में कांग्रेस को 45.73 प्रतिशत मत प्राप्त हुए थे। अर्थात पीछले चुनाव की तुलना में इस चुनाव में कांग्रेस को 5.15 प्रतिशत कम मत प्राप्त हुए।

चौथी विधानसभा आम चुनाव 1967

राज्य विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के पुनः सीमांकन के बाद वर्ष 1967 में राजस्थान विधानसभा के सदस्यों/स्थानों की कुल संख्या 184 निर्धारित की गई।[13] प्रदेश की चौथी विधानसभा के गठन के लिए कुल 184 स्थानों के लिए आम चुनाव वर्ष 1967 में सम्पन्न हुए। इस चुनाव में 8 राजनीतिक दलों के 456 उम्मीदवारों सहित 436 निर्दलिय उम्मीदवारों अर्थात कुल 892 उम्मीदवारों ने सहभागिता की। कांग्रेस ने राज्य विधानसभा के कुल 184 स्थानों में से 89 स्थान, जनसंघ ने 22 स्थान, ए.डब्यू.टी. ने 49 स्थान, समयुक्त समाजवादी पाटऍ ने 8 स्थान, सी.पी.आई ने 1 स्थान एवं निर्दलिय उम्मीदवारों ने 15 स्थान प्राप्त किये। कांग्रेस ने राज्य विधानसभा के कुल 184 स्थानों में से 48.36 प्रतिशत स्थानों पर जीत दर्ज की।[14] यदि मतदान की द्वष्टि से देखा जाये तो कांग्रेस ने कुल वैध मतदान (67,56,056) में से 41.41 प्रतिशत (27,98,204) मत प्राप्त किये।[15] जो पीछले चुनाव (1962) की तुलना में 1.43 प्रतिशत आधिक है।

पांचवी विधानसभा आम चुनाव 1972

प्रदेश की पांचवी विधानसभा के गठन के लिए कुल 184 स्थानों के लिए आम चुनाव वर्ष 1972 में सम्पन्न हुए। इस चुनाव में कुल 875 उम्मीदवारों ने सहभागिता की, जिसमें विभिन्न राजनीतिक दलों उम्मीदवारों की संख्या 520 तथा निर्दलिय उम्मीदवारों की संख्या 355 रही। कांग्रेस ने राज्य विधानसभा के कुल 184 स्थानों में से 145 स्थानों पर सफलता प्राप्त की। इससे अलावा जनसंध ने 8 स्थान, एस.डब्लू.टी. ने 11 स्थान, समाजवादी दल ने 4 स्थान, सी.पी.आई. ने 4 स्थान, कांग्रेस (ओ) ने 1 स्थान एवं निंदलियों ने 11 स्थान प्राप्त किये।[16] कांग्रेस ने विधानसभा के कुल 184 स्थानों में से 78.80 प्रतिशत (145) स्थानों पर सफलता प्राप्त की है जबकि गत चुनाव 1967 में कांग्रेस ने 48.36 प्रतिशत (89) स्थानों पर सफलता प्राप्त की थी। कांग्रेस ने इस चुनाव में 56 स्थानों की बढत करते हुए कुल 145 स्थानों पर जीत दर्ज की।

यदि मत प्राप्ति की द्वष्टि से देखा जाये तो कांग्रेस ने इस चुनाव में विभिन्न उम्मीदवारों को प्राप्त कुल वैध मतों में से 51.14 प्रतिशत (39,76,157) मत प्राप्त किये। कांग्रेस ने गत चुनाव में 41.41 प्रतिशत (27,98,204) मत प्राप्त किये थे और इस चुनाव में 9.73 प्रतिशत की बढत करते हुए कुल 51.14 प्रतिशत

मत प्राप्त किये। कांग्रेस ने इस चुनाव में स्थान एवं मत प्राप्ति दोनों ही द्वष्टि से बढत प्राप्त की है। जो प्रदेश में कांग्रेस के प्रति मतदान व्यवहार के अत्यधिक झुकाव का प्रतिक है। यह झुकाव सम्भवतः राष्ट्रीय नेतृत्व श्रीमति इंदिरा गांधी के प्रति था। 1971 के लोकसभा के मध्यावधि चुनाव में श्रीमति इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने अपूर्व सफलता प्राप्त की। अपूर्व सफलता की इस कहानी को कांग्रेस ने प्रदेश में भी दोहराया। प्रदेश विधानसभा की कुल 184 सीटों में से 145 सीटों पर जीत दर्ज की।

छठी विधानसभा आम चुनाव 1977

प्रदेश की छठी विधानसभा की कुल 199 सीटों के लिए आम चुनाव वर्ष 1977 में सम्पन्न हुए। इस चुनाव में उम्मीदवारों की कुल संख्या 1146 रही, जिसमें राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों की संख्या 423 एवं निर्दलिय प्रत्याशियों की संख्या 723 रही। चुनाव परिणामों के अनुसार इस चुनाव में जनता पाटऍ ने कांग्रेस को शिकस्त देते हुए बहुमत प्राप्त किया। राज्य विधानसभा के 199 स्थानों में से जनता पाटऍ को 150 सीटें, कांग्रेस को 41 सीटें, सी.पी.आई. को 1 सीट, सी.पी.एम. को 1 सीट एवं निर्दलियों को 6 सीटें प्राप्त हुई। राजस्थान की राजनीति में ऐसा प्रथम बार हुआ जब किसी गैर-कांग्रेसी दल को बहुमत की प्राप्ती हुई। कांग्रेस को मात्र 20.60 प्रतिशत (41) सीटों पर ही संतोष करना पड़ा। जनता पाटऍ ने विधानसभा की 75.37 प्रतिशत (150) सीटें प्राप्त कर जीत का रिकार्ड दर्ज किया।

यदि मत प्राप्ति की दृष्टि से देखा जाये तो जनता पाटऍ ने इस चुनाव में कुल वैध मतदान (8209306) में से 50.41 प्रतिशत (41,38,296) मत प्राप्त किये तथा कांग्रेस ने 31.41 (25,78,702) मह प्राप्त किये।[17] प्रदेश के लोकतान्त्रिक राजनीतिक इतिहास में यह प्रथम अवसर अथवा चुनाव रहा, जब मतदाताओं ने अपना विश्वास एक ऐतिहासिक राजनीतिक दल के स्थान पर एक नई पाटऍ में व्यक्त किया। मतदाताओं ने अपना समर्थन कांग्रेस दल के स्थान पर जनता पाटऍ को दिया। ऐसा ही परिवर्तन राष्ट्रीय राजनीती में भी देखा गया और श्रीमती इन्दिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस को पराजय का मुँह देखना पड़ा। श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा देश में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने के कारण वह बहुत अलोकप्रिय हुई और चुनाव में हार के रूप में उन्हें उसकी कीमत चुकानी पडी।[18] भारतीय जनता ने आपातकाल के विरुद्ध मतदान कर राजनीतिक जागरूकता और लोकतन्त्र के प्रति अपनी प्रतिबद्धता का परिचय दिया।

सातवीं राजस्थान विधानसभा चुनाव 1980

प्रदेश की सातवीं विधानसभा के गठन में लिए कुल 200 सीटों के लिए आम चुनाव वर्ष 1980 में सम्पन्न हुए। इस चुनाव में उम्मीदवारों की कुल संख्या 1406 रही, जिसमें विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों की संख्या 651 एवं निंदलीय उम्मीदवायों की संख्या 755 रही। चुनाव परिणामों के अनुसार कांग्रेस ने बहुमत प्राप्त कर सŸाा में वापसी की। कांग्रेस में विधानसभा की 200 सीटों में से 133 सीटें प्राप्त करने में सफल रही।

यदि मत प्राप्ति की दृष्टि से देखा जाये तो कांग्रेस ने कुल वैध मतदान (92,52,664) में से 42.96 प्रतिशत (39,75,215) मत प्राप्त किये। अर्थात कांग्रेस (आई) ने मतदाताओं में अपने प्रति खोये हुए विश्वास को पुनः जाग्रत करने में सफल रही। गत चुनाव (1977) में कांग्रेस ने कुल मतों में से 31.41 प्रतिशत मत अणजत किये थे जबकि इस चुनाव (1980) में कांग्रेस ने 42.96 प्रतिशत मत प्राप्त किये। इसके अतिरिक्त कांग्रेस (यू) ने 6 सीटें, भाजपा ने 32 सीटें, जनता दल (जे.पी.) ने 8 सीटें, जे. पी. (एस) 7 सीटें, सी.पी.आई. ने 1 सीट, सी.पी.एम. ने 1 सीट एवं निर्दलीयों ने 12 सीट प्राप्त की।[19] कांग्रेस ने राज्य विधानसभा की 200 सीटों में से 66.5 प्रतिशत (133) सीट प्राप्त करने में सफलता अणजत की। गत चुनाव (1977) में कांग्रेस ने 41 सीट प्राप्त की थी, जबकि इस चुनाव (1980) में कांग्रेस 92 सीटों पर बढ़त बनाते हुए 133 सीटों पर सफलता प्राप्त की। प्रदेश एवं केन्द्र सत्ता में कांग्रेस की शानदार वापसी के लिए मतदाताओं में श्रीमती इन्दिरा गांधी के नेतृत्व की स्वीकार्यता तथा गैर कांग्रेस सरकार की कमजोरी प्रमुख कारण रही।

आठवी विधानसभा आम चुनाव 1985

प्रदेश की आठवी विधानसभा के गठन के लिए 198 सीटों के लिए आम चुनाव वर्ष 1985 में सम्पन्न हुए। इस चुनाव में उम्मीदवारों की कुल संख्या 1485 रही, जिसमें विभिन्न राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों की संख्या 508 एवं निर्दलीय उम्मीदवारों की संख्या 977 रही। चुनाव परिणामों के अनुसार कांग्रेस ने विधानसभा में 113 स्थान, भाजपा ने 38 स्थान, एल.डी. ने 27 स्थान, जे. पी. ने 10 स्थान, सी.पी.एम. ने 1 स्थान एवं निर्दलीय उम्मीदवारों ने 9 स्थान प्राप्त किये।

यदि मत प्राप्ति की दृष्टि से देखा जाये तो कांग्रेस ने कुल वैध मतदान (11365612) में से 46.79 प्रतिशत मत (5318026) प्राप्त किये।[20] आठवीं विधानसभा में काग्रेस को सातवी विधानसभा में प्राप्त स्थानों (133) से 20 स्थान कम अर्थात 113 स्थान प्राप्त हुए, लेकिन मत प्राप्ति की दृष्टि से गत चुनाव (1980) की तुलना में 3.83 प्रतिशत की बढ़त प्राप्त की। अर्थात इस चुनाव में कांग्रेस ने कुल वैध मतों के 46.79 प्रतिशत मत प्राप्त किये। 31 अक्टूबर 1984 को श्रीमती इन्दिरा गांधी की हत्या के कारण जनता में उपजी सहानुभूति के फलस्वरूप कांग्रेस के वोट बैंक में बढ़त हुई।

नवीं विधानसभा आम चुनाव 1990

प्रदेश की नवीं विधानसभा के गठन के लिए आम चुनाव वर्ष 1990 में सम्पन्न हुए। इस चुनाव में उम्मीदवारों की कुल संख्या 3088 रही, जिसमें विभिन्न राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों की संख्या 590 तथा निर्दलीय उम्मीदवारों की संख्या 2498 रही। चुनाव परिणामों के अनुसार गत सत्तासीन कांग्रेस दल विधानसभा में सीटों की दृष्टि से पीछड कर तीसरे स्थान पर आ गया। इस चुनाव में भाजपा ने 85 स्थान, कांग्रेस ने 50 सीटें, जनता दल ने 55 सीटे, सीपीआई(एम) 1 सीट तथा अन्य निर्दलीय उम्मीदवारों ने 9 सीटें प्राप्त की।[21]

यदि मत प्राप्ति की दृष्टि से देखा जाये तो ज्ञात होता है कि भाजपा ने अपने जनाधार में वृद्वि की। गत चुनाव 1985 में इसे 20.16 प्रतिशत मत प्राप्त हुए थे जबकि इस चुनाव (1990) में उसे 25.25 प्रतिशत मतों की प्राप्ति हुई। भाजपा के सम्बन्ध में यह तथ्य महत्वपूर्ण है कि भाजपा ने प्रत्येक चुनाव में अपने जनाधार को बढ़ाया। विधानसभा आम चुनाव में (1980) में 18.60 प्रतिशत, चुनाव 1985 में 20.16 प्रतिशत तथा वर्तमान चुनाव (1990) में 25.25 प्रतिशत मतों की प्राप्ति यह दर्शाता है कि भाजपा मतदान व्यवहार को प्रभावित करने में सफल रही। जबकि कांग्रेस का जनाधार कम हुआ। गत विधानसभा चुनाव 1985 में कांग्रेस को 46.79 प्रतिशत मतों की प्राप्ति हुई थी और इस विधान सभा चुनाव में यह 35.61 प्रतिशत रह गया। अर्थात कांग्रेस दल को इस चुनाव में 13.15 प्रतिशत मतों का खामियाजा उठाना पड़ा। इस चुनाव में यह विशेष बात रही कि कांग्रेस (33.64 प्रतिशत) मतों की द्वष्टि भाजपा (25.25 प्रतिशत) से आगे होते हुए भी सीट प्राप्त करने में पीछे रही।

दसवीं विधानसभा आम चुनाव (1993-1998)

प्रदेश की दसवीं विधान के गठन के लिए आम चुनाव वर्ष 1993 में सम्पन्न हुए। इस चुनाव में उम्मीदवारो की कुल संख्या 2451 रही, जिनमें विभिन्न राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों की संख्या 567 तथा निर्दलीय उम्मीदवारों की संख्या 1884 रही। चुनाव परिणामों के अनुसार गत सत्तासीन भाजपा पुनः कांग्रेस दल से आगे रही। भाजपा विधानसभा की 96, कांग्रेस 76 सीटें, सी.पी.आई.(एम) 1, जनता दल 6 तथा निर्दलीय उम्मीदवार 21 सीटें प्राप्त करने में सफल रहे।[22] यदि मत प्राप्ति की —ष्टि से देखा जाये तो ज्ञात होता है कि भाजपा अपना जनाधार बढाने में सफल रही। इस चुनाव में भाजपा को 38.60 प्रतिशत मत प्राप्त हुए जबकि पीछले चुनाव (1990) में भाजपा ने 25.25 प्रतिशत मत प्राप्त किये थे। कांग्रेस दल ने भी अपने जनाधार में वृद्धि की। पीछले चुनाव (1990) में कांग्रेस दल ने 33.64 प्रतिशत मत प्राप्त किये थे और इस चुनाव में कांग्रेस दल को 38.27 प्रतिशत मत प्राप्त हुए।

ग्यारहवीं विधानभा आम चुनाव (1998-2003)

प्रदेश की ग्यारहवीं विधानसभा (1998-2003) के गठन के लिए आम चुनाव वर्ष 1998 में सम्पन्न हुए। इस चुनाव में उम्मदवारों की कुल संख्या 1439 रही, जिनमें विभिन्न राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों की संख्या 834 एवं निर्दलीय उम्मीदवारों की संख्या 605 रही। चुनाव परिणामों के अनुसार कांग्रेस ने विधानसभा की 150 सीटों पर जीत दर्ज करते हुए सत्ता में वापसी की। नवल्र एवं दसवीं विधानसभा में कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई थी और दोनों विधानसभा काल 1990-1993 एवं 1993-1998 में भाजपा सरकार बनाने में सफल रही है लेकिन इस चुनाव (1998) में भाजपा सरकार बनाने में असफल रही और वह मात्र 33 सीटों पर सीमट कर रह गई। इसके अतिरिक्त बसपा राज्यविधान सभा की 2 सीट, सी.पी.आई.(एम) 1, जनता दल 3, अन्य पंजीकृत दल 1 सीट तथा निर्दलीय उम्मीदवार 7 सीटें प्राप्त करने में सफल रहे।[23]

यदि मत प्राप्ति की दृष्टि से देखा जाये तो ज्ञात होता है कि कांग्रेस एवं भाजपा में मात्र 11.56 प्रतिशत मतों का अन्तर रहा। इस चुनाव में कांग्रेस ने कुल वैध मतों (18834911) में से 44.87 प्रतिशत अर्थात 84,67,160 मत तथा भाजपा ने 33.23 प्रतिशत मत प्राप्त किये।

बारहवीं विधानसभा आम चुनाव वर्ष 2003

राजस्थान प्रदेश की बारहवीं विधानसभा (2013-2018) के गठन में लिए आम चुनाव वर्ष 2003 में सम्पन्न हुए। इस चुनाव में उम्मीदवारों की कुल सख्या 1541 रही, जिसमें विभिन्न राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों की संख्या 985 तथा र्निदलीय उम्मीदवारों की संख्या 556 रही। चुनाव परिणामों के अनुसार 120 सीटें प्राप्त कर भाजपा ने सत्ता में वापसी की जबकि गत सत्ताधारी दल कांग्रेस को विपक्ष में बैठकर सन्तोष करना पड़ा। कांग्रेस 56 सीट, बसपा 2 सीट, माकपा 1 सीट, लोकदल 4 सीट, जनता दल (यू) 2, एल.जे.एस.पी. 1 सीट, आर.एस.एन.एम. 1 सीट तथा निर्दलीय 13 सीटें प्राप्त करने में सफल रहे।[24]

यदि मत प्राप्ति की दृष्टि से देखा जाये तो ज्ञात होता है कि भाजपा एवं कांग्रेस में मत प्राप्ति की द्वष्टि से मात्र 3.55 प्रतिशत का अन्तर रहा। इस चुनाव में वैध मतदान (2,27,80,053) में से भाजपा को 39.20 प्रतिशत (8929572) एवं कांग्रेस को 35.65 प्रतिशत मत (8120605) प्राप्त हुए। सीट प्राप्ति की द्वष्टि से भले ही भाजपा कांग्रेस से अधिक सीटें प्राप्त करने में सफल रही लेकिन मतदान व्यवहार को कांग्रेस के विरूद्ध भी नही कहा जा सकता क्योंकि मत प्राप्ति की द्वष्टि से दोनों दलों में कोई विशेष अन्तर नही रहा।

तेरहवी विधानसभा आम चुनाव 2008

प्रदेश की **तेरहवी** विधानसभा के गठन के लिए आम चुनाव वर्ष 2008 में सम्पन्न हुए। इस चुनाव में उम्मीदवारों की कुल सख्या 2194 रही, जिसमें राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों की संख्या 1169 तथा निर्दलीय उम्मीदवारों की संख्या 1025 रही। चुनाव परिणामों के अनुसार भाजपा 78 सीटें, कांग्रेस 96 सीटें, माकपा 3 सीटें, बसपा 6 सीटें, अन्य राजनीतिक दल 3 सीटें तथा निर्दलीय उम्मीदवार 14 सीटें प्राप्त करने में सफल रहे।[25] यदि मत प्राप्ति की दृष्टि से देखा जाये तो ज्ञात होता है कि इस चुनाव में कुल वैध मतदान (2,40,98,682) में से भाजपा को 34.27 प्रतिशत (82,58,966) एवं कांग्रेस को 36.82 प्रतिशत मत (88,72,184) प्राप्त हुए। इसके अतिरिक्त बसपा को 7.60 प्रतिशत (18,32,195), सीपीआई को 0.22 प्रतिशत (52,294) मत, सीपीएम को 1.65 प्रतिशत (3,92,438) मत, एनसीपी को 0.30 प्रतिशत (72,281) मत, अन्य पंजीकृत दलों को 4.20 प्रतिशत

(10,11,913) मत तथा निर्दलीय उम्मीदवारों को 14.97 प्रतिशत (36,06,411) मत प्राप्त हुए। इस चुनाव में कांग्रेस भाजपा से 2.55 प्रतिशत (6,13,218) मत अधिक प्राप्त कर 19 सीटें अधिक प्राप्त करने में सफल रही।

चौदहवीं विधानभा आम चुनाव 2013

प्रदेश की चौदहवीं विधानसभा के गठन के लिए आम चुनाव 2013 में सम्पन्न हुए। इस चुनाव में उम्मीदवारों की कुल सख्या 2096 रही, जिसमें विभिन्न राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों की संख्या 1338 तथा निर्दलीय उम्मीदवारों की संख्या 758 रही। चुनाव परिणामों के अनुसार भाजपा 163 सीटें, कांग्रेस 21 सीटें, बसपा 3 सीटें, नेशनल पिपुल्स पार्टी 4 सीटें, जमीदार पार्टी 2 सीट तथा निर्दलीय उम्मीदवार 7 सीटें प्राप्त करने में सफल रहे।[26] यदि मत प्राप्ति की दृष्टि से देखा जाये तो ज्ञात होता है कि इस चुनाव में कुल वैध मतदान (3,02,70,703) में से भाजपा को 46.05 प्रतिशत (1,39,39,203) मत, तथा कांग्रेस को 33.71 प्रतिशत (1,02,04,694) मत प्राप्त हुए। इसके अतिरिक्त बसपा को 3.44 प्रतिशत (10,41,241), सीपीआई को 0.18 प्रतिशत (55,256) मत, सीपीएम को 0.89 प्रतिशत (2,69,002) मत, एनसीपी को 0.23 प्रतिशत (70,874) मत, अन्य पंजीकृत दलों को 7.13 प्रतिशत (21,57,209) मत तथा निर्दलीय उम्मीदवारों को 8.37 प्रतिशत (25,33,224) मत प्राप्त हुए।

विभिन्न विधानसभा चुनावों में भाजपा को प्राप्त मतों की द्वष्टि से यह चुनाव ऐतिहासिक रहा क्योंकि भाजपा ने इस चुनाव में श्रेष्ठ प्रर्दशन करते हुए 46.05 प्रतिशत मत प्राप्त किये। ज्ञातव्य है कि सातवीं, आठवीं, नवीं, दसवीं, ग्यारहवीं, बारहवीं एवं तेरहवीं विधानसभा आम चुनाव में भाजपा ने क्रमशः 18.60 प्रतिशत, 21.16 प्रतिशत, 25.25 प्रतिशत, 38.60 प्रतिशत, 33.31 प्रतिशत, 39.20 प्रतिशत, 34.27 प्रतिशत, एवं 46. 05 प्रतिशत मत प्राप्त किये। भाजपा के वोट बैंक में अत्यधिक वृद्धि इस बात का सूचक है कि भाजपा मतदान व्यवहार को प्रभावित करने में सफल रही। भाजपा के द्वारा प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में श्री नरेन्द्र मोदी के नाम की घोषणा तथा श्री नरेन्द्र मोदी का बहेतर चुनाव प्रचार चौदहवीं विधानसभा के आमचुनाव 2013 में भाजपा की सफलता का मुख्य कारण रहा।

पन्द्रहवीं विधानभा आम चुनाव 2018

चुनाव परिणामों के अनुसार भाजपा 73 सीटें, कांग्रेस 100 सीटें, बसपा 6 सीटें, सीपीएम 2 सीटें, अन्य पंजीकृत पार्टी 6 सीट तथा निर्दलीय उम्मीदवार 13 सीटें प्राप्त करने में सफल रहे। यदि मत प्राप्ति की —ष्टि से देखा जाये तो ज्ञात होता है कि इस चुनाव में कुल वैध मतदान (3,02,70,703) में से भाजपा को 39.28 प्रतिशत मत, तथा कांग्रेस को 39.82 प्रतिशत मत प्राप्त हुए। इसके अतिरिक्त बसपा को 4.08 प्रतिशत, सीपीएम को 1.23 प्रतिशत मत, सीपीआई को 0.12 प्रतिशत मत, एनसीपी को 0.19 प्रतिशत मत, अन्य पंजीकृत दलों को 5.68 प्रतिशत मत तथा निर्दलीय उम्मीदवारों को 9.59 प्रतिशत मत प्राप्त हुए।[27]

राजस्थान की पहली विधानसभा के गठन के लिए सम्पन्न प्रथम आम चुनाव-1952 से लेकर अब तक 15 विधानसभाओं का गठन हो चुका है। अर्थात प्रदेश में आज तक 15 आम चुनाव हो चुके हैं। इन चुनावों में प्रदेश के मतदाताओं ने बढ-चढकर सहभागिता की। चुनाव में मतदाता की सहभागिता मतदान व्यवहार को इंगित करती है। विधानसभा के गठन के लिए सम्पन्न विभिन्न आम चुनावों में मतदान प्रतिशत में उतार-चढाव प्रदेश के मतदाताओं के मतदान व्यवहार को प्रर्दशित करता है।

निष्कर्ष

निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि राजनीतिक व्यवस्था में जनता की भागीदारी सुनिश्चित करने और लोकतन्त्र को सुदृढ़ करने में चुनाव की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि इसी प्रक्रिया के माध्यम से व्यक्ति (नागरिक) और व्यवस्था (राजनीतिक व्यवस्था) के मध्य अन्तःक्रिया सम्पन्न होती है। चुनाव के अन्तर्गत मतदान द्वारा ही नागरिक शासन की नीतियों और कार्यों के प्रति अपनी सहमति अथवा विरोध प्रकट करते हैं। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव ही लोकतंत्र को मजबूत बनाते हैं। अर्थात् स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव ही नागरिकों को यह अवसर उपलब्ध करवाते हैं कि वह एक मतदाता के रूप में अपने मताधिकार का प्रयोग कर सरकार को पुरूस्कृत या दण्डित करें। लोकहितकारी सरकार जो अपना मत एवं समर्थन देकर पुनः सत्ता में आने या अवसर दे अथवा जन विरोधी सरकार के विरूद्ध मतदान कर उसे बहुमत प्राप्त करने से रोके। इस प्रकार मतदान व्यवहार निर्वाचन व्यवस्था की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया ही नहीं बल्कि मतदाता की राजनीतिक अनुभूतियों के प्रति प्रतिक्रिया व्यक्त करने का एक माध्यम भी है। मतदान व्यवहार समकालीन लोकतान्त्रिक राजनीति की एक

महत्वपूर्ण संकल्पना है और इसके अध्ययन के द्वारा ही प्रतिनिधि लोकतंत्र की सफलता को सुनिश्चित किया जा सकता है।

सन्दर्भ सूची

1. पपली राम, मतदान व्यवहार, जाति एवं राजनैतिक चेतना, आविष्कार पब्लिशर्स, जयपुर, 2015, पृ. 85
2. संजीव महाजन, सामाजिक मनोविज्ञान, अर्जुन पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली, 2004, पृ. 439
3. एन.जी.एस. किनी, दी सिटी वोटर इन इण्डिया, 1974, पृ. 27
4. स्टोक्स, डोनाल्ड ई. वोटिंग इन डेविड शिल्स (संपा) वॉ.16, पृ. 387
5. बबीता चौधरी, 16 वीं लोकसभा निर्वाचन और मतदान व्यवहार, रिसर्च रिइन्फोर्समेन्ट, वर्ष 2, अंक-2, नवम्बर 2014-अप्रेल 2015, पृ. 191
6. ऋचा बंसल, नोट- 6, पृ.8
7. संजय लोढ़ा 'जनप्रतिनिधियों की सीरत, जनमत एवं लोकतंत्र' मूलप्रश्न मई-जुलाई, 2010, पृ. 13
8. 12वीं विधानसभा जनरल इलेक्शन -2003, इलेक्शन डिपार्टमेन्ट, राजस्थान, जयपुर सारणी गग , पृ. 125 पर आधारित
9. राजस्थान विधानसभा इलेक्शन 1952 (पाटर्ॅ पोजिशन 1952 टू 1993, स्टेटिकल रिपोर्ट, जनरल इलेक्शन, 1998, पृ. 28)के आधार पर
10. राजस्थान विधानसभा इलेक्शन 1957, पृ. 28
11. प्रेमकुमार श्रीवास्तव, रतन सिंह चौहान, सुरेन्द्र श्रीवास्तव, राजस्थान वार्षिकी, राजस्थानी ग्रन्थागार, जोधपुर 1997, पृ. 103
12. राजस्थान विधानसभा इलेक्शन 1962, पृ. 28
13. पपली राम, नोट- 1, पृ. 145
14. राजस्थान विधानसभा इलेक्शन 1967, पृ. 29
15. राजस्थान विधानसभा इलेक्शन 1972, पृ. 29
16. इतिहास में आज का दिन, दैनिक भास्कर, अलवर, 18 जनवरी 2017, पृ. 11

17. जैन, पुखराज एवं फड़िया, बी. एल. ''भारतीय शासन एवं राजनीति'' साहित्य भवन, आगरा उ.प्र. पृ. 692
18. राजस्थान विधानसभा इलेक्शन 1980, पृ. 30
19. राजस्थान विधानसभा इलेक्शन 1985, पृ. 30
20. राजस्थान विधानसभा इलेक्शन 1990, पृ. 29
21. राजस्थान विधानसभा इलेक्शन 1993, पृ. 29
22. राजस्थान विधानसभा इलेक्शन 1998, पृ. 29
23. राजस्थान विधानसभा इलेक्शन 2003, फोर्टिन विधानसभा इलेक्शन 2013
24. राजस्थान, स्टेटिकल इनफारमेशन, रिपोर्ट, इलेक्शन डिपार्टमेंट, राजस्थान
25. राजस्थान विधानसभा इलेक्शन 2008, पृ. 108
26. राजस्थान विधानसभा इलेक्शन 2013, पृ. 108
27. 15 वीं विधानसभा इलेक्शन 2018, राजस्थान मैनेजमेंट ऑफ इलेक्शनस् एण्ड स्टेटिकल इनफारमेशन, चीफ इलेक्शन आफीसर, राजस्थान, पृ. 23